साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 18-24 सितंबर 2023 वर्ष-9, अंक-23

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

राष्ट्रपति ने किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का किया उद्घाटन

-देसी बीजों को बचाने वाले किसानों को 10-10 लाख का दिया अवॉर्ड

मप्र की लहरी बाई को मिला पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान

» द्रौपदी मुर्मू ने कहा-किसानों को असाधारण शक्ति और जिम्मेदारी दी गई

भोपाल। जागत गांव हमार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के सी. सुब्रामण्यम ऑडिटोरियम में हुआ। राष्ट्रपति ने मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले की कृषक लहरी बाई को श्रीअन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान प्रदान किया। लहरी बाई को कृषक अधिकार वैश्विक संगोष्ठी के अलंकरण समारोह में सम्मान स्वरूप 1,50,000 रुपए की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदाय किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित थे।

डिंडोरी जिले की बजाग तहसील निवासी लहरी बाई ने बैगा समुदाय की सहायता से कोदो, कुटकी, सांवा, काग, सिकिया, मडुआ जैसे दुर्लभ श्रीअन्न प्रजातियों का सीड बैंक विकसित किया है। दिल्ली में 12 से 15 सितंबर, 2023 तक चलने वाली वैश्विक संगोष्ठी में लहरी बाई ने अपने सीड बैंक की प्रदर्शनी भी लगाई है। वहीं मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल ने लहरी बाई की अभूतपूर्व उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मिलेट्स संरक्षण के लिए लहरी बाई द्वारा अद्भुत कार्य किया गया है। उनके कार्य की सराहना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मन की बात में कर चुके हैं। लहरी बाई ने सम्पूर्ण मप्र को गौरवान्वित किया है।

-मानवता के साथ ही पूरे ग्रह को बचा रही किसान बिरादरी

-कृषि इकोसिस्टम के अस्तित्व के लिए महती आवश्यकता

कृषक समुदाय फसल विविधता के सच्चे संरक्षक

राष्ट्रति ने कहा कि दुनिया का कृषक समुदाय इसका अग्रणी संरक्षक है और वे फसल विविधता के सच्चे संरक्षक हैं। किसानों को असाधारण शक्ति और जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम सभी को पौधों और प्रजातियों की विभिन्न किस्मों की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें पुनर्जीवित करने के किसानों के प्रयास की सराहना करनी चाहिए, इन वनस्पतियां अस्तित्व हम सभी के लिए बहुत अहम है।

भारत की समृद्ध कृषि

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विविधता से भरपूर एक विशाल देश है, जिसका क्षेत्रफल विश्व का केवल 2.4 प्रतिशत है। विश्व के पौधों की विभिन्न किस्मों और जानवरों की सभी दर्ज प्रजातियों का 7 से 8 प्रतिशत भारत में मौजूद है। जैव विविधता के क्षेत्र में भारत पौधों और प्रजातियों की विस्तृत श्रृंखला से संपन्न देशों में से एक है। भारत की यह समृद्ध कृषि-जैव विविधता वैश्विक समुदाय के लिए अनुपम निधि रही है।

पारंपरिक किस्मों का पोषण किया

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे किसानों ने कड़े परिश्रम और उद्यमिता से पौधों की स्थानीय किस्मों का संरक्षण किया है, जंगली पौधों को अपने अनुरूप बनाया है। पारंपरिक किस्मों का पोषण किया है, इससे फसल प्रजनन कार्यक्रमों को आधार मिला है और इससे मनुष्यों और पशुओं के लिए भोजन और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास ने भारत को 1950-51 के बाद से खाद्यान्न, बागवानी, मत्स्य पालन, दूध और अंडे के उत्पादन को कई गुना बढ़ाने में योगदान दिया है।

किसान हमारी भूमि के संरक्षक

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि-जैव विविधता संरक्षण सिर्फ कर्तव्य नहीं है, बल्कि इकोसिस्टम के अस्तित्व के लिए महती आवश्यकता है। भारत के पौधा किस्म संरक्षण ढांचे की विशेषताओं में से एक, इसका किसानों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारी समृद्ध कृषि विरासत, किसानों के प्रयासों के कारण फली-फूली है, जिन्होंने कई पौधों की किस्मों का पोषण व विकास किया है। ये किस्में न केवल जीविका स्रोत हैं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति के बीच गहरे संबंध का जीवंत प्रमाण हैं।

सहकारिता मंत्री भदौरिया बोले- इंदौर या भोपाल में खुलेगा

मध्यप्रदेश में शुरू होगा पहला सहकारिता विवि

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू होगा। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने भोपाल में वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में यह जानकारी दी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर हुई चर्चा में मध्यप्रदेश के इंदौर अथवा भोपाल में विश्वविद्यालय शुरू करने के उनके प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। बहुत जल्द ही मध्यप्रदेश में सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू होगा। विश्वविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र के अनेक विषयों के पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाएगा और सहकारिता संबंधी अनुसंधान भी होगा।

सहकारिता मंत्रालय

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि देश में आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता आंदोलन को मजबूती देते हुए केन्द्रीय सरकार में सहकारिता मंत्रालय शुरू किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य भी अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर उन्हें लाभांवित करना है।

बीज संघ सदस्यों के सुझाव पर अमल होगा

इधर, सहकारिता मंत्री ने कहा है कि राज्य बीज संघ की साधारण सभा की बैठक में सदस्यों द्वारा दिये गये सभी सुझावों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने प्रबंध संचालक बीज संघ के प्रबंध संचालक एके सिंह को निर्देशित किया कि सदस्यों के सुझाव पर विचार कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साधारण सभा की बैठक में वर्ष 2023-24 में प्रजनक बीज उठाव, वितरण एवं आधार-प्रमाणित बीज के उत्पादन और वितरण की प्रगति की जानकारी दी गई।

कवायद: चुनाव से पहले सरकार देगी बड़ी राहत, मौसम की बेरुखी देख अब कर्ज माफ करने की तैयारी

किसान क्रेडिट कार्ड! तीन लाख तक का कर्ज माफ करेगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष जहां लोगों को गारंटी दे रही है। वहीं सत्तारुढ़ बीजेपी भी हर वर्ग लुभाने के लिए खजाना खोल दिया है। चाहे लाड़ली बहना योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, किसानों की बिजली बिल माफी हो या फिर कर्मचारियों को परमानेंट करने की घोषणा। सरकार ने चुनाव से पहले खजाना खोल दिया है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस आधी आबादी यानी महिला और किसान हैं। यही वजह है कि वह महिलाओं के लिए एक के बाद एक घोषणा कर रही है। वहीं सरकार के एजेंडे में किसान भी हैं।

प्रदेश में किसानों का 12 हजार मिल रही सम्मान निधि

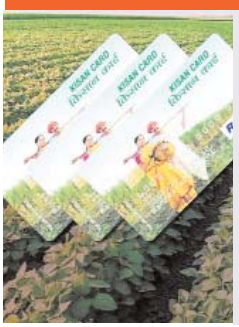

यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों को हर साल दिए जा रहे 6 हजार रुपए के साथ मध्यप्रदेश सरकार की ओर से भी 6 हजार रुपए वार्षिक देना शुरू कर दिया है। हालांकि, पहले मप्र में किसान सम्मान निधि के रूप में सिर्फ 4 हजार रुपए ही दिए जा रहे थे। अब यह राशि बढ़ा दी गई है। यानी मप्र के किसानों को साल में 12 हजार रुपए मिल रहे हैं। सूत्रों की मानें तो शिवराज सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की किसान कर्जमाफी का तोड़ निकालने की तैयारी में हैं। सरकार किसानों को खुश करने के लिए कर्ज पर ब्याज पहले ही माफ कर चुकी है। मौसम की बेरुखी को देख अब किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज माफ करने की तैयारी में है। सूत्रों की मानें तो सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 से 5 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जा सकता है।

आचार संहिता लागू होने पहले सरकार कर सकती है राहत की घोषणा

माना जा रहा है कि सरकार यह ऐलान आचार संहिता लागू होने पहले कर सकती है। प्रदेश की भाजपा सरकार पिछले चुनाव से सबक लेते हुए इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि शिवराज सरकार हर हाल में किसान, महिला और गरीब वर्ग के साथ आदिवासियों को खुश रखना चाहती है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी कई राहत भरी घोषणाएं कर सकते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सभी में यहां तक कहा था कि अभी भी उनकी कमान में बहुत सारे तीर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ऐन वक्त पर ऐसी घोषणाएं कर एक बहुत बड़े वर्ग को साधने में सफल हो सकते हैं।

पांच हजार रुपए वर्दी भत्ता और 1000 रुपए पौष्टिक आहार भत्ता मिलेगा

-सीएम की महावत, कटर जैसे अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों से होगी चर्चा

जंगल-जानवर की सुरक्षा में तैनात शहीद कर्मचारी के परिवार को मिलेंगे 25 लाख

» राज्य वन शहीद स्मारक का लोकार्पण, चंदनपुरा नगर वन का शुभारंभ किया

» वन महोत्सव में शामिल हुए और वन शहीदों के परिजनों का किया सम्मान

भोपाल। जागत गांव हमार

वन और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा में शहीद होने वाले वन विभाग के कर्मचारियों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी। वन विभाग के अमले को 5 हजार रुपए वर्दी भत्ता और 1000 रुपए का पौष्टिक आहार भत्ता भी दिया जाएगा। वन विभाग के महावत, कटर जैसे अल्प वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों की मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाकर उनकी समस्याओं के निराकरण और कल्याण एवं बेहतरी के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में प्रति वर्ष राष्ट्र वन शहीद दिवस उद्देश्यपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणाएं यहां राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर राज्य वन शहीद स्मारक के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने चंदनपुरा नगर वन का वर्चुअली शुभारंभ भी किया।

मुख्यमंत्री ने वन विभाग को प्रदेश में फारेस्ट कवर को बढ़ाने में उनके योगदान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश जंगलों की रक्षा करने वाला प्रदेश है। मुख्यमंत्री नवनिर्मित वन भवन में आयोजित वन महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने 44 शहीद वन कर्मियों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी तथा शाल-श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया।

पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत के रास्ते पर चलना होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरे यह सिद्ध करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया को भारत के बताए रास्ते पर ही चलना होगा। मत्स्य-पुराण में कहा गया है कि दस कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। भारतीय संस्कृति में वृक्ष को ईश्वर, पिता और दस पुत्रों के बराबर माना गया है। हम तुलसी, पीपल, आंवला को काटना अशुभ मानते हैं। यदि पेड़-पौधे नहीं रहेंगे तो मानव जीवन भी नहीं रहेगा।

अनुभूति का विमोचन

मुख्यमंत्री का वन मंत्री शाह ने अश्वगंधा का पौधा भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने नगर वन चंदनपुरा, वन शहीद स्मारिका 2023, मध्यप्रदेश के समस्त नगर वन की स्मारिका और मध्यप्रदेश ईको टूरिज्म बोर्ड की गतिविधियों पर केंद्रित पुस्तिका अनुभूति का विमोचन किया। चंदनपुरा नगर वन पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ।

वन सम्पदा का बखूबी संरक्षण किया

सीएम शिवराज ने कहा कि मध्यप्रदेश ने वन सम्पदा का बखूबी संरक्षण किया है। देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्यप्रदेशमें है, जो राज्य के क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत और देश के कुल वन क्षेत्र का 12.30 प्रतिशत है। वन्य-प्राणियों की सुरक्षा में भी हम आगे हैं। मध्यप्रदेश देश का टाइगर स्टेट तो है ही यहां तेंदुआ, घड़ियाल, गिध्दों की संख्या भी पर्याप्त है,साथ ही चीतों का भी पुनर्स्थापन हुआ है।

वन कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वनों की सुरक्षा की, राष्ट्र उनका ऋणी है। वन कर्मी अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में खतरों के बीच अपने कर्तव्य निभाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

प्रदेश में वन और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून की जरूरत

वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश को परिवार मानकर चला रहे हैं। उनकी संवेदनशील कार्य-प्रणाली से सभी वर्गों का कल्याण हो रहा है। मंत्री ने प्रदेश में वन और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा के लिए अधिक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता बताई तथा सम्पूर्ण वन भवन, वन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री का आभार माना।

बारिश की कमी से सूखी फसल, अब झमाझम ने किसानों की बढ़ाई परेशानी

खरगोन में 'सफेद सोने' की खान पर लगी नजर

खरगोन। जागत गांव हमार

पूरे देश में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन खरगोन जिले में ही होता है। यहां बीटी कपास की पैदावार होती है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। इस साल जिले में 2 लाख 5 हजार से ज्यादा हेक्टेयर से किसानों ने कपास की बोवनी की है, लेकिन अब लगता है कि सफेद सोने की इस खान पर किसी की नजर लग गई है। जिले में बारिश नहीं होने से किसानों को फसलें खराब होने की चिंता सता रही है। जो किसान बारिश पर ही निर्भर है, उनकी फसलें तो लगभग चौपट होने की कगार पर है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से जिले में बारिश नहीं हुई है। तेज धूप होने से खेतों में जमीन की नमी खत्म हो गई। फसलें सूख कर मुरझा गईं। पौधों की ग्रोथ पूरी तरह रुक गई, जो फूल खिले थे वो भी टूटकर गिर गए। कई तरह की बीमारियां लग गई हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि बीच में कुछ हिस्सों में बारिश हुई, लेकिन तब तक फसल चौपट हो चुकी थी।

लागत भी निकलना मुश्किल

किसान विष्णु पाटीदार बताते हैं की कपास की खेती कुदरती खेती है। यह पूरी तरह बारिश पर आधारित है। समय पर बारिश होती है तो पैदावार भी अच्छी होती है, लेकिन अभी लंबे समय से बारिश नहीं हुई है ऐसे में फसलें सूख गई गई। स्थिति यह है की फसल लगाने में जो लागत लगी थी, वो भी अब निकलना मुश्किल है। एक बीघा में एक क्विंटल कपास भी आ जाएं तो बड़ी बात होगी। अब फसल इस स्थिति में आ गई है की अगर अब बारिश होती भी है तो फसलें सड़ जाएगी।

पानी की कमी से फसलों की ग्रोथ रुकी

किसानों का कहना है की जो ड्रिप लगाकर खेती करते है। उनकी फसलों की स्थिति थोड़ी ठीक है, लेकिन जो किसान सिर्फ बारिश, नहरों या तालाबों पर आधारित है, उनकी तो पूरी फसल ही खराब हो गई है। किसान अगर घंटो तक मोटर चलाकर सिंचाई करते है तो इसमें खर्च बहुत आएगा। जो हर किसान वहन नहीं कर पाएगा जबकि वैकल्पिक साधन जुटाकर सिंचाई करने से फसलों की वो ग्रोथ भी वैसी नहीं होगी जैसी बारिश से होती है।

बीमारियों से बुरा हाल

किसान लोकेंद्र सिंह मंडलोई बताते हैं की उन्होंने 5 एकड़ खेत में कपास की बोवनी की है, लेकिन समय पर बारिश नहीं होने से फसलों की हाइट बढ़ाना बंद हो गई है। साथ ही कई तरह की बीमारियां भी लग गई है, जो फसलों को बर्बाद कर रही है। तेज धूप ओर उमस से फसलों में तेलिया, मुंगवा जैसी कई तरह की बीमारियां लग रही है। जिससे कपास की फसल खराब हो रही है। अगर वैकल्पिक तौर पर सिंचाई करते भी है तो ये बीमारियां खत्म नहीं होंगी, क्योंकि ये बीमारियां सिर्फ बारिश के पानी से ही खत्म होती हैं। धूप इतनी है की दवाइयां भी छिड़कते है तो वो भी काम नहीं कर रहा।

फसलों को पानी की जरूरत

महिला किसान शारदा बाई बताती है की उन्होंने अपने 4 बीघा खेत में कपास की बोवनी की है। पौधे पानी की मांग कर रहे है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में फसलें मुरझा रही है, पौधों पर जो पुड़िया (फूल) बनी थी वो सब गिर गई है। बीमारियों ने फसलों को जकड़ लिया है। सफेद मकड़ी और इल्लियां पौधों को खा रही हैं। अभी वें वैकल्पिक तौर पर पानी दे रहे है, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा है।

हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे में कम लागत, श्रम की बचत के साथ लंबे समय तक कमाई कराने वाली कटहल की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है।

कटहल की खेती | एक बार लगाकर कई साल तक कमाई

विटामिन और मिनरल से भरपूर स्वाद

भोपाल। कटहल में विटामिन और मिनरल अच्छी मात्रा होती है। इसमें विटामिन सी, विटामिन बी 6, नियासिन जैसे कई विटामिन मिलते हैं। इसके साथ ही कटहल में कैल्शियम, सोडियम, आयरन, फास्फोरस, पोटैशियम व जिंक जैसे मिनरल्स भी होते हैं। कटहल को सदाबहार फसल भी कहा जाता है। इसकी खेती किसी भी मौसम में की जा सकती है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, यूपी के अलावा भी कई अन्य राज्यों में कटहल की खेती की जाती है। दोमट मिट्टी को कटहल की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कटहल के खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी जरूरी है।

किसान कटहल की खेती करने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें। अब खाद के रूप में खेत में गोबर डालें अब एक समान दूरी पर गड्ढे खोदकर कटहल के पौधे लगा दें। 15 दिन हो जाने के बाद किसान भाई खेत की सिंचाई करें। किसान खाद के तौर पर वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप अपने बाग में बीज सहित कटहल की खेती कर रहे हैं, तो 6 वर्ष में फल आने शुरू हो जाएंगे। उधर गूटी तरीके से खेती करने पर बेहद कम समय में ही कटहल के बाग में फल आ जाते हैं। एक हेक्टेयर में कटहल के करीब 140 से लेकर 150 तक पौधे लगाए जाते हैं। किसान एक हेक्टेयर में ही कटहल की खेती कर लाखों रुपये की कमाई कर सकते हैं।

कटहल की उन्नत किस्में

» कटहल की कुछ उन्नत किस्मों में खजवा, सिंगापुरी, रूद्राक्षी , स्वर्ण मनोहर और स्वर्ण पूर्ति आदि किस्में शामिल हैं। इन किस्मों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।

» **खजवा किस्म:** कटहल का खजवा किस्म सब्जी की बजाय फल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसके फल जल्दी पक जाते हैं। ये किस्म उच्च पैदावार देने के लिए जाना जाता है। वहीं इसके एक फल का वजन 25 से 30 किलो होता है, इसके फल पकने के बाद सफेद, मुलायम और रसीले हो जाते हैं।

» **स्वर्ण मनोहर:** कटहल की यह किस्म अधिक पैदावार वाली होती है। इसके पेड़ तो छोटे होते हैं, लेकिन फल अधिक संख्या में लगते हैं। फल लगने के 20-25 दिन बाद ही पेड़ से सब्जी के लिए अच्छी संख्या में कटहल तोड़कर बेचे जा सकते हैं।

» **स्वर्ण पूर्ति किस्म:** कटहल की यह किस्म सब्जी के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके फल छोटे आकार के कम रेशे और बीज वाले होते हैं। इसलिए इसकी सब्जी स्वादिष्ट बनती है। इसके फल देर से पकते हैं। यह सब्जी के लिए एक उपयुक्त किस्म है। इसका फल छोटा यानी तीन से चार किलो का होती है। इस किस्म के फल देर से पकने के कारण लंबे समय तक सब्जी के रूप में उपयोग किये जा सकते हैं।

» **सिंगापुरी किस्म:** इस किस्म के पौधों को पके हुए फल के तौर पर अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसके पौधे रोपाई के सात से 10 साल बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके पोधों से निकलने वाले फलों का गूदा देखने में पीला और स्वाद में मीठा होता है। इसके फल का वजन सात से 10 किलो तक का होता है।

» **रूद्राक्षी किस्म:** इस किस्म के एक कटहल का वजन लगभग पांच किलो का होता है। यह सब्जियों के लिए सबसे उपयुक्त किस्म माना जाता है। दक्षिण भारत में इसकी व्यापक रूप से खेती की जाती है।

ध्यान रखें कि कई बार पौधे सही ढंग से नहीं लगते हैं, इसलिए उन्हें पर्याप्त पानी देना जरूरी

नींबू की खेती, कम लागत में किसानों को सालों साल मुनाफा

भोपाल। नींबू का इस्तेमाल हर घर में होता है। दाल-सब्जी में डालने से ये उसका जायका बढ़ा देता है। नींबू देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब्जियों में से भी एक है। इसकी खेती करना किसानों के लिए बेहद फायदे का सौदा साबित हो सकती है। नींबू का दाम बाजार में 100 रुपए प्रति किलो चलता है। लेकिन कभी-कभी इसके दाम भी आसमान छूने लग जाते हैं। हालांकि इसकी डिमांड बाजार में बराबर रहती है। नींबू की खेती कर किसान भाई शानदार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिस नींबू का रंग नारंगी जैसा होता है वह दूसरे नींबू की तुलना में अधिक खट्टा होता है। इस नींबू का प्रयोग सब्जी में डालने से लेकर अचार बनाने तक में होता है। इसकी डिमांड अधिक रहती है साथ ही किसानों को इसकी फसल बेचकर बढ़िया मुनाफा होता है।

नींबू की खेती करने से पहले, खेत को पूरी तरह से तैयार करना जरूरी है। पौधों को लगाते समय करीब 1 फीट गहरा गड्ढा खोदें। इस गड्ढे में पानी डालकर छोड़ दें। जब पानी सूख जाए, तो पौधा लगाने के लिए मिट्टी डालें और पौधे के चारों ओर से घेरा बनाकर एक गोल कियारी बनाएं। इसके बाद किसान भाई उसमें पानी डालें। इस दौरान ध्यान रखें कि कई बार पौधे सही ढंग से नहीं लगते हैं, इसलिए उन्हें पर्याप्त पानी देना जरूरी होता है।

सालों तक मिलता है लाभ

नींबू के पौधे लगाने के तीन से साढ़े तीन वर्ष के बाद ही फल निकलने शुरू हो जाते हैं। एक पौधे से एक साल में बाजार के आधार पर तीन हजार किलो का उत्पादन होता है। नींबू का बगीचा एक बार लगाने पर 30 साल तक फल देता है, जिसका मतलब ये है कि किसान भाई 30 वर्ष तक इसका लाभ ले सकते हैं। नींबू की खेती कर किसान भाई कुछ ही साल में लाखों रुपए तक का मुनाफा पा सकते हैं।

खेती करने का सबसे सही समय

जुलाई और अगस्त का महीना नींबू के पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय माना जाता है। इसको लगाने के लिए गड्ढे की खुदाई एक घन मीटर की करनी चाहिए। इसके बाद गड्ढे में 10-15 दिनों तक धूप लगने के बाद अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर गड्ढे में डालकर भर देना चाहिए। जैसे ही जुलाई की पहली बरसात होती है आप लाइम और लेमन दोनों का रोपण कर सकते हैं। दूरी लगभग 4 से 4.5 मीटर आप रख सकते हैं। शुरुआत के एक से दो सालों में नींबू के बाद आप अपने खेत में दूसरी फसलें भी लगा सकते हैं।

नींबू की उन्नत किस्में

भारतीय कृषि संस्थान पूसा ने कागजी नींबू (लाइम) और लेमन दोनों की ही दो-दो प्रजातियां विकसित की हैं। जहां तक कागजी नींबू यानी लाइम की बात है, तो पूसा उदित, और पूसा अभिनव दो प्रजातियां हैं, जिन्हें उत्तर भारत में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। वहीं इनके फल का समय जुलाई, अगस्त और फरवरी से अप्रैल के बीच में होता है। जहां तक लेमन फल की बात है। लेमन की दो प्रजातियां पूसा संस्थान ने विकसित की हैं। कागजी कला जो बहुत ही पुरानी किस्म है और हाल ही में पूसा लेमन वन एक प्रजाति विकसित हुई है, जो लगभग 20 जून के आसपास पककर तैयार हो जाती है। जहां तक इनके रोपण का सवाल है, तो उत्तर भारत में इन दोनों को ही सफलता-पूर्वक उगाया जा सकता है।

नामुमकिन को मुमकिन बनाने का दूसरा नाम है नरेन्द्र मोदी

कमल पटेल
मंत्र, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, मप्र

देश के दिल में मप्र है और प्रदेशवासियों के मन में मोदी बसते हैं। पीएम मोदी से देश का बच्चा-बच्चा प्यार करता है। प्रधानमंत्री, मध्यप्रदेशवासियों से बहुत प्यार करते हैं। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अब तक श्री मोदी प्रदेश की लगभग 30 यात्राएँ कर चुके हैं। हर यात्रा में प्रदेशवासियों को सौगातें मिलती हैं। प्रदेश का हर शख्स प्रधानमंत्री से मिले स्नेह से गौरवान्वित है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का दूसरा नाम है नरेन्द्र मोदी। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर नमन करते हुए आधुनिक भारत के नव-निर्माण के साथ वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को साकार रूप देने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ग्रहण करने के बाद से ही अपने संकल्प को पूरा करने का जो बीड़ा उठाया है, उसे परिश्रम की पराकाष्ठा कर पूरा कर रहे हैं। आज पूरे देश के साथ मध्यप्रदेश में भी विकास की बयार बह रही है। आजादी का अमृत काल चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश को एतिहासिक और अविस्मरणीय उपलब्धियों की सौगातें दी हैं। कई राष्ट्रीय योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश से किया है। प्रधानमंत्री ने 6 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में हरदा जिले को नंबर-1 आने पर बधाई दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने 14 सितंबर को सागर जिले के बीना में 51 हजार करोड़ रूपये की परियोजनाओं का शिलान्यास कर प्रदेशवासियों को अभूतपूर्व सौगात दी, इससे क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी का प्रदेश के प्रति असीम प्रेम है कि उन्होंने एक जुलाई 2023 को प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश में एक करोड़ से अधिक पीवीसी आयुष्मान कार्डों का वितरण प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री ने देश में साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा डिजिटल आयुष्मान कार्ड का टैब का बटन दबा कर वितरण किया। उन्होंने सिकल सेल नेशनल पोर्टल, मिशन प्रबंधन गाइड-लाइन, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिये आयुष्मान प्रशिक्षण मॉड्यूल, गैर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिये जागरण मॉड्यूल और बीमारी से पीड़ित बच्चों के माता-पिता के लिये मॉड्यूल का भी विमोचन किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पूरे देश में मनाई जायेगी। रानी दुर्गावती की वीरगाथा को याद करने के लिये फिल्म बनाई जायेगी, चांदी का सिक्का निकाला जायेगा, पोस्टल स्टॉम्प जारी किया जायेगा और घर-घर प्रेरणा अभियान चलाया जायेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार निरंतर जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिये कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश की धरती से 15 नवम्बर को हर वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून 2023 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी

दिखाकर रवाना किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2023 को मध्यप्रदेश के रीवा से राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 लाख 11 हजार हितग्राहियों को वर्चुअली गृह प्रवेश कराया है। उन्होंने ई-ग्राम स्वराज और ई-जैम इकीकृत पोर्टल का लोकार्पण भी कर मध्यप्रदेश वासियों को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 17 हजार करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया।

प्रदेश में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने के बाद अब तक प्रदेश में साढ़े चार लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनी है। सिंचाई क्षमताओं का विस्तार हुआ है, 98 लाख गरीबों को मकान, 82 लाख गैस कनेक्शन, 80 लाख किसानों को सम्मान निधि, एक करोड़ 15 लाख लोगों को राशन, 3 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड और 25 लाख लोगों को मुफ्त इलाज दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश के साथ प्रदेश भी बदल रहा है।

प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2022 को श्योपुर जिले के नेशनल पार्क कूनो में अफ्रीका के नामीबिया से लाये गये चीतों को पुनर्स्थापित (छोड़ा) कर प्रदेश को चीता स्टेट का गौरव प्रदान किया।

प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया। उज्जैन में आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं और महाकाल लोक अद्भुत छवि को निहार रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2021 को भोपाल में 450 करोड़ रूपये की लागत से देश में पहली बार पीपीपी मॉडल पर पुनर्विकसित किये गये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ने भोपाल, मध्यप्रदेश में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री ने उज्जैन और इंदौर के बीच दो नई मेमू ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने रानी कपलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल-नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे-भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 23 जून 2018 को इंदौर से 37 करोड़ रूपये लागत की भोपाल के न्यू-मार्केट की मल्टी लेवल पार्किंग, 62 करोड़ 36 लाख रूपये लागत की सीहोर की 2 परियोजनाओं, 4 हजार 700 करोड़ की नगरीय विकास परियोजनाओं का ई-लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री का मध्यप्रदेश के प्रति और मध्यप्रदेशवासियों का प्रधानमंत्री से स्नेह बरकरार है। प्रधानमंत्री 18 सितंबर सोमवार को ओंकारेश्वर में स्थापित की जा रही आदि शंकराचार्य की एकात्म प्रतिमा का वर्चुअली लोकार्पण कर राष्ट्र को सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में 25 सितंबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक बार फिर हम सब के बीच रह कर हमें सौगातें देंगे।

अधिक उपज के लिए जैविक उर्वरक का महत्व

» **डॉ. विशाल मेश्राम**
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक
कृषि विज्ञान केन्द्र नरसिंहपुर
» **डॉ. निधि वर्मा,** वैज्ञानिक (सस्य विज्ञान)
» **डॉ. आशुतोष शर्मा,** वैज्ञानिक (कृषि वानिकी)
» **डॉ. आरएस शर्मा,** वैज्ञानिक (पौध सरंक्षण)
» **विजय सिंह सूर्यवंशी**
कृषि विज्ञान केन्द्र नरसिंहपुर

यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब ये सूक्ष्म जीवाणु मृदाओं में उपस्थित हैं, तो फिर जैव उर्वरकों की आवश्यकता क्यों है। या हर वर्ष इनका उपयोग क्यों आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी स्थानों पर नत्रजन स्थिरीकरण एवं स्फुर घोलक सूक्ष्म जीवों की प्रभावशाली प्रजातियां उपस्थित हों किन्ही किन्ही परिस्थितियों में इनकी संख्या बहुत कम होती है, जिससे अपेक्षाकृत कम लाभ मिलता है, या फिर ये जीवाणु अप्रभावशील होते हैं। अर्थात इनकी नत्रजन स्थिरीकरण या स्फुर घोलक क्षमता नगण्य रहती है। गर्मियों के दौरान उच्च तापक्रम अत्याधिक वर्षा या अन्य विषम परिस्थितियां भी इन जीवाणुओं की संख्या कम करने के लिए उत्तरदायी रहती हैं।

जैव उर्वरक ही एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा मृदा में प्रभावशाली जीवाणुओं का उचित संख्या में निशेधन किया जाता है, जिससे ये सूक्ष्मजीव पूर्ण क्षमता से कार्य करते है। अत: जैव उर्वरकों का उपयोग प्रतिवर्ष अति आवश्यक है।

भारत वर्ष में उत्पादित एवं प्रचलित जैव उर्वरक निम्न है- नत्रजनीय जैव उर्वरक

1. सहजीवी नत्रजन स्थिरीकरण-राइजोबियम एवं एजोला। **2.** सह पार्श्व नत्रजन स्थिरीकरण-एजोस्पायरिलम। **3.** असहजीवी नत्रजन स्थिरीकरण-एजोटोबेक्टर, ऐसीटोबेक्टर एवं नीलहरित शैवाल

राइजोबियम जैव उर्वरक: इस जैव उर्वरक में प्रभावशाली राइजोबियम जीवाणुओं का संग्रहण होता है जो दलहनीय फसलों की जड़ों में प्रभावी गठाने बनाकर अधिकतम वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण करते हैं। सामान्यत: भूमि में अप्रभावशील राइजोबियम जीवाणु उपस्थित रहते है एवं वे जड़ों पर गठाने भी बनाते हैं, परंतु उनकी वायुमंडलीय नत्रजन स्थिरीकरण की क्षमता बहुत नगण्य होती है। अत: जैव उर्वरकों के माध्यम से प्रभावशाली जीवाणु प्रदाय किए जाते हैं, जिनमें अधिक वायुमंडलीय नत्रजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। इस जैव उर्वरक की यह विशेषता है कि सहजीवी पौधे को स्थिरीकृत नत्रजन का लाभ तो मिलता ही है, परंतु जड़ की गठाने विघटित हो जाती है तो मृदा में अवशेष नत्रजन मिल जाती है जो अगली फसल को प्राप्त होती है।

राइजोबियम जीवाणु की विभिन्न प्रजातियां होती हैं एवं प्रत्येक प्रजाति एक विशेष दलहनी फसलों की जड़ों पर ही गठाने बनाती हैं। अत: विभिन्न दलहनी फसलों के लिए अलग-अलग राइजोबियम जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि राइजोबियम कल्चर के पैकेट पर जिस दलहनी फसल का नाम अंकित है, उसी दलहनी फसल पर उसका उपयोग करना चाहिए। किसी अन्य दलहनी फसल का उपयोग करने पर पौधों की जड़ों में गठानों का निर्माण नही होता है एवं नत्रजन स्थिरीकरण भी नहीं होता है।

एजोटोबेक्टर एवं एजोस्पायरिलम जैव उर्वरक: इन जैव उर्वरकों में क्रमश: एजोटोबेक्टर एवं एजोस्पायरिलम जीवाणुओं का संग्रह होता है। ये जीवाणु स्वंतत्र रूप से या पौध जड़ों के समीप सामंजस्य से वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण करते हैं। एजोटोबेक्टर मृदा में पूर्णत: स्वंतत्र रुप से रह कर बिना किसी सहजीविता के वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण करते है जबकि एजोस्पायरिलम जीवाणु पौधे की जड़ों के समीप सामंजस्य के साथ वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण करते हैं। नत्रजन स्थिरीकरण के साथ साथ ये जीवाणु कुछ पौध वृद्वि सवंर्धक जैसे- इंडोल एसिटिक एसिड एवं जिब्रेलिक एसिड भी मृदा में उत्सर्जित करते हैं, जो पौध वृद्वि में सहायक होते हैं।

नत्रजन स्थिरीकरण में राईजोवियम का योगदान

फसल	नत्रजन कि./है.
अरहर	168-200
चना	85-110
लोबिया	80-85
मूंगफली	50-60
मसूर	90-100
मूंग/उड़द	50-55
मटर	52-77
सोयाबीन	60-80

खेत में डाले गये नत्रजन रासायनिक उर्वरक की मात्रा का 30 से 35 प्रतिशत ही पौधो को प्राप्त होता है। इन उर्वरकों की कीमतें लधु एवं सीमांत कृषकों की पहुंच से बाहर होती जा रही है इन परिस्थितियों में कल्चर के उपयोग में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करते हुए भूमि को उपजाऊ एवं स्वस्थ्य रखा जा सकता है। एजोटोबेक्टर से प्राप्त नत्रजन की कीमत प्रति किलो 50 पैसे से कम आती है जबकि रासायनिक उर्वरक से प्राप्त नत्रजन की कीमत प्रति किलो 6 रुपये से भी अधिक है।

एजोटोवेक्टर जैव उर्वरक: एजोटोबेक्टर जैव उर्वरक जीवाणुओं की प्रभावशाली प्रजातियां (ए.क्राकोरम एव ए. एलिजिस) का उपयुक्त वाहक पदार्थ में सवर्धन एवं संग्रहण है यह कल्चर पौधों के जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रुप से रहते हुये वायुमंडलीय नत्रजन को स्थिरीकृत कर पौधों को नत्रजन उपलब्ध कराता है यह कल्चर विशेष रुप से अनेक धान्य फसलों जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, कोदो, कुटकी, कपास, सूरजमुखी, गन्ना और शाक सब्जियों के लिये लाभकारी पाया गया है।

विश्व ओजोन दिवसः इतिहास, तिथि एवं इस वर्ष की थीम

हम सभी हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पूरी दुनिया में मनाने के लिए चिह्नित किया गया है। आज दुनिया भर में मनाया जाने वाला यह दिवस हमारी धरती के सुरक्षा कवच के रूप में काम करने वाली ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। यह दिन हम सभी को ओजोन के विकास को समृद्ध और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। ओजोन परत हमें हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, और इस परत को अत्यधिक रासायनिक क्षति से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आज हम उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो इस विश्व ओजोन दिवस 2023 में प्रदर्शित होंगे। हम इस दिन के इतिहास, महत्व और थीम पर भी प्रकाश डालेंगे।

विश्व ओजोन दिवस 2023 तिथि: इस दिन को मनाने के लिए 16 सितंबर को चुना गया है। आपको बता दे चलें कि साल 1987 में जब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादन पर रोक लगाने के लिए एक वैश्विक समझौता हुआ। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। इसके प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत की रक्षा करना जिसे सभी देशों ने स्वीकार किया था। विश्व ओजोन दिवस को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं में से एक माना जाता है जो चर्चा का विषय होता है। पृथ्वी पर पड़ने वाली किरणों से ओजोन परत ही लोगों को सुरक्षित रखती है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी की सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है और इसके बिना हम बिल्कुल भी स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए, हमें अपनी ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के लिए उचित पहल करनी होगी। आइए हम विश्व ओजोन दिवस 2023 के इतिहास और महत्व के साथ सभी महत्वपूर्ण विचारों पर प्रकाश डालें।

विश्व ओजोन दिवस 2023 का इतिहास: 22 मार्च, 1985 को ओजोन परत की रक्षा के लिए वियना कन्वेंशन में एक प्रस्ताव रखा गया जिसे बाद में स्वीकार भी किया गया। यह प्रस्ताव ओजोन परत के माध्यम से एक छेद की खोज के बाद शुरू किया गया है। प्रस्ताव को अपनाने के साथ, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर, 1987 को लागू किया गया था। 1994 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके विश्व ओजोन परत दिवस के अवलोकन को स्वीकार किया।

विश्व ओजोन दिवस का महत्व: विश्व ओजोन दिवस 2023 पर हम ओजोन परत के लाभों पर प्रकाश डालेंगे। इसकी हानिकारक संरचना हमारे विश्व के लिए एक बड़ी हानि हो सकती है। इस परत को हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए कई स्तर पर हिस्सा लेना होगा।

विश्व ओजोन दिवस 2023 के बारे में प्रमुख तथ्य: ओजोन परत सूर्य की लगभग 98प्रतिशत यूवी किरणों को अवशोषित करने में सक्षम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वह रासायनिक तत्व है जो ओजोन परत को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। 1985 के दौरान अंटार्कटिका में ओजोन परत के चारों ओर एक छेद खोजा गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के आसपास ओजोन छिद्र धीरे-धीरे सिकुड़ने के संकेत दे रहा है। सीएफसी जैसे ओजोन को नष्ट करने वाले रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में अपनाया गया था।

पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रही दुनिया को राहत देने वैज्ञानिकों ने एक नया समाधान खोज निकाला

विद्युतीकृत सब्जियां और फसलें जल्द ही एक आम बात बन जाएंगी

फसल को दिए जा रहे बिजली के झटके ज्यादा पैदावार लेने के लिए नया तरीका

भोपाल। जागत गांव हमार

खेती में लागत कम करके ज्यादा उत्पादन लिया जाए इस दिशा में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं। पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रही दुनिया को राहत देने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया समाधान खोज निकाला है। हालांकि, ये तरीका अभी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरी दुनिया के किसान पर्यावरण को बेहतर बनाने और पैदावार को बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। दरअसल, वैज्ञानिकों ने नई तरह की खेती तकनीक विद्युत बागवानी की दिशा में कई प्रयोग किए हैं। कई देशों में शोधकर्ता पर्यावरणीय असर को कम करते हुए कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने के लिए बिजली की क्षमता की खोज कर रहे हैं।

इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्लांट मॉर्फोजेनेसिस प्रयोगशाला में एक परियोजना के तहत वर्टिकल फार्मिंग को बदलने के लिए इलेक्ट्रोड से युक्त हाइड्रोजेल क्यूब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ट्रांसल्यूसेंट क्यूब्स में मौजूद नेटवर्कस्ट्रक्चर तरलता को बरकरार रखता है, जिसमें छोटी एयर टनल्स से हरी पत्तियां निकलती हैं। प्रयोग के तहत हाइड्रोजेल क्यूब्स में बिजली के झटकों की छोटी-छोटी खुराक दी जा रही है।

दुनिया में दूर हो सकता है खाद्य संकट

खेती किसानी के क्षेत्र को लेकर दुनिया भर में हर दिन नए-नए प्रयोग और शोध किए जाने से फसल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों में लगातार बदलाव हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिजली के एकीकरण से कृषि को ज्यादा टिकाऊ और उत्पादक बनाने में बड़ी मदद मिल सकती है। उनका कहना है कि दुनियाभर में चल रहे अनुसंधानों और प्रयोगों के साथ विद्युतीकृत सब्जियां व फसलें जल्द ही एक आम बात बन सकती हैं। इससे खेती के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम करते हुए वैश्विक खाद्य संकट का समाधान पेश किया जा सकता है।

तेज अंकुरण, ज्यादा पैदावार

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पहल कृषि में विद्युत हस्तक्षेप की दिशा में वैश्विक आंदोलन का हिस्सा है। पिछले दशक से वैज्ञानिक खेती के लिए बिजली की ताकत का इस्तेमाल करने के अलग-अलग तरीकों पर प्रयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने तेज अंकुरण के लिए बीजों को बिजली के झटके देने से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट करके पैदावार बढ़ाने तक के प्रयोग किए हैं। यही नहीं, पौधों की वृद्धि को तेज करने के लिए नियंत्रित बिजली यानी ठंडे प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा चुका है।

दूर हो सकती है पर्यावरणीय चिंता

वैज्ञानिकों का कहना है कि खेती में बिजली की ताकत इस्तेमाल करने का मकसद पारंपरिक कृषि के कारण पैदा होने वाली पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना है। दरअसल, दुनियाभर में पारंपरिक खेती की वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बड़ी हिस्सेदारी है। सिंथेटिक उर्वरक उत्पादन प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि खेती में बिजली की ताकत का इस्तेमाल मिट्टी के कटाव और बढ़ती आबादी को स्थायी रूप से भोजन कराने की जरूरतों से जुड़ी चुनौतियों का भी समाधान करेगा।

पैदावार में 20 से 75 फीसदी तक की बढ़ोतरी

विद्युत कृषि का सबसे आकर्षक पहलू फसल की पैदावार बढ़ाने की क्षमता है। अब तक अध्ययनों में वैज्ञानिकों को उत्साहजनक नतीजे हासिल हुए हैं। फसल के आधार पर पैदावार में 20 से 75 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए, एक मिनट से भी कम समय तक बीजों को ठंडे प्लाज्मा से ट्रीटमेंट देने से आलू की पैदावार में 40 फीसदी की वृद्धि हुई। विद्युत कृषि को लेकर उत्साह के बावजूद कुछ लोग इसके विरोध में हैं।

पूरी दुनिया में फैल जाएगी तकनीक

वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये तकनीक कामयाब रही तो बहुत जल्द इसे पूरी दुनिया में फैला दिया जाएगा। दरअसल, वैज्ञानिक इस तकनीक को शानदार बता रहे हैं, उनका कहना है कि इसकी मदद से वो वैश्विक खाद्य संकट से भी निपट सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसके उपयोग से सब्जिया केमिकल मुक्त होंगी जो सेहत के लिए बेहतर होगा। वहीं भारत और चीन जैसे देश के लिए जहां जनसंख्या ज्यादा है ये तकनीक बेहद लाभदायक होगी। किसान इस तकनीक की मदद से अपने खेतों के साथ साथ छोटी छोटी जगहों पर भी भारी मात्रा में सब्जियां उगा पाएंगे। यहां तक की अर्बन किसान जो टेरिस गार्डन में खेती करते हैं, उनके लिए भी ये तकनीक काफी मददगार साबित होगी।

अंदर विटामिन बी, पोटैशियम, कॉपर और मैग्नीशियम

सफेद बैंगन की खेती किसानों को करेगी मालामाल

भोपाल। जागत गांव हमार

बैंगन की खेती कम समय में ज्यादा फायदा देने के लिए जानी जाती है है। इस समय बाजार में सफेद बैंगन की मांग बढ़ रही है, जिसकी खेती पूरे साल भर की जा सकती है। इसकी खेती किसानों को कम समय में ज्यादा मुनाफा दिला सकती है।

विटामिन और मिनरल्स अधिक मात्रा में - बता दें कि सफेद बैंगन में सामान्य बैंगन के मुकाबले अधिक मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इस के अंदर विटामिन बी, पोटैशियम, कॉपर और मैग्नीशियम सहित कई तरह के पोषक तत्व भी रहते हैं। इसी कारण इसके पत्ते और तने दवाई बनाने के काम भी आते हैं।

कैसे करें खेती- यदि किसान सफेद बैंगन उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें इसकी नर्सरी तैयार करनी होगी। नर्सरी तैयार करने के लिए खेतों की कई बार जुताई करनी चाहिए। फिर, जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो खेत को गारे से समतल कर दिया जाता है। इसके बाद क्यारी बनाकर उसमें सफेद बैंगन के बीज बो दें। फिर सिंचाई के बाद क्यारी को पुआल से ढक दें। इस दौरान निराई-गुड़ाई भी करते रहें। इस प्रकार एक माह बाद सफेद बैंगन की पौध तैयार करने की तैयारी पूरी हो जायेगी। इसके बाद आप बैंगन के पौधों को नर्सरी से उखाड़कर दो फीट की दूरी पर तैयार खेत में लगा सकते हैं।

शानदार कमाई

यदि आप सफेद बैंगन का पौधा फरवरी माह में लगाएंगे तो जून से इसमे बैंगन लगने शुरू हो जाएंगे। बैंगन लगाने के बाद उन्हें हर 20 दिन में पानी दें। यदि ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाए तो बेहतर होगा। बैंगन के पौधे बड़े होते हैं और उन्हें सहारे की जरूरत होती है, इसलिए इसके आधार के पास एक बांस की छड़ी गाड़ दें और तने को उससे बांध दें। बैंगन की कीमते बाजार में 60 से 80 रुपए किलो रहती हैं। यदि आप एक एकड़ जमीन में सफेद बैंगन की खेती करते हैं तो लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं।

ड्रेगन फ्रूट की खेती कर किसानों के लिए मिसाल बने कटंगी के भूपेंद्र

बालाघाट। जागत गांव हमार

बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के ग्राम सीताखो के युवा किसान भूपेन्द्र शरणागत ड्रेगन फ्रूट की खेती कर अन्य किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। भूपेन्द्र वर्ष 2021 से ड्रेगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं।

43 वर्षीय भूपेन्द्र बताते हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में पढ़ाई की है। उनका परिवार लम्बे समय से खेत में धान, गेहूं और चना की खेती करता आ रहा था। उन्होंने यह महसूस किया कि खेती की लागत से ज्यादा उन्हें लाभ नहीं हो रहा है। परिवार की सीमित आय को देखते हुए उन्होंने कुछ नया करने का विचार किया। उनके एक भाई नार्वे में रहते हैं। भाई की तरफ से उन्हें ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की सलाह मिली। फिर उन्होंने गोंदिया जिले के रायपुर स्थित किसान बालचन्द्र ठाकुर के फार्म जाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती की जानकारी ली।

भूपेन्द्र ने शुरुआत में 50 डिस्मिल खेत में ड्रेगन फ्रूट की खेती प्रारंभ की। उन्होंने बताया कि ड्रेगन फ्रूट की खेती के लिए खेत में एक निश्चित दूरी पर छोटे-छोटे बांस के खंबे लगाए जाते हैं। इन खंभों पर अंगूर की खेती की तरह ही ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए जाते हैं। एक खंमे पर 4 पौधे लगाए जाते हैं। ड्रेगन फ्रूट मूलत: अमेरिका का फल है और कैक्टस प्रजाति का पौधा है। एक बार इसका पौधा लगाने पर वह 25 सालों तक फसल देता है। किसान भूपेन्द्र बताते हैं कि ड्रेगन फ्रूट की खेती पर 10 लाख रूपये की लागत लगा चुके हैं। इस वर्ष उन्हें 50 डिस्मिल के खेत में 3 क्विंटल ड्रैगन फ्रूट की पैदावार मिली है। यह फसल 200 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से आसानी से घर बैठे बिक जाती है।

भूपेन्द्र का इरादा ड्रेगन फ्रूट की खेती को बढ़ा कर 2 एकड़ तक करने का है। इसमें एक हजार पौधे लगाएंगे जिससे प्रति एकड़ 7 टन ड्रेगन फ्रूट का उत्पादन मिलेगा। वे खेत में जैविक खाद का ही उपयोग कर रहे हैं। ड्रेगन फल एंटी आक्सीडेंट के साथ फेट रहित और उच्च फायबर युक्त होता है। इसके सेवन से पाचन तंत्र और ह्म्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। इस वजह से इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है।

सरकार की साप्ताहिक रिपोर्ट में खुलासा: केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने खरीफ सीजन का जारी किया रकबा

तिलहन-दलहन के रकबे में बड़ी गिरावट भारत में धान और गन्ने का रकबा बढ़ा

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने खरीफ सीजन का रकबा जारी किया है। 15 सितंबर को जारी रकबे की साप्ताहिक रिपोर्ट में बताया गया है कि धान की रोपनी में इस हफ्ते लगभग 11 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। देश में इसका नॉर्मल रकबा 399.45 लाख हेक्टेयर होता है। 2023 में अब तक 409 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो चुकी है जबकि पिछले साल इसी अवधि में 398 लाख हेक्टेयर में खेती हुई थी। दूसरी ओर दलहन फसलों की बोवनी में साढ़े छह लाख हेक्टेयर की गिरावट आई है। दलहन फसलों का रकबा देखें तो अरहर की बुआई में लगभग ढाई लाख हेक्टेयर की कमी आई है। पिछले साल 45.81 लाख हेक्टेयर में खेती हुई थी जबकि इस साल अभी तक 43.21 लाख हेक्टेयर में बोवनी हुई है। उड़द दाल की बात करें तो इसमें में 0.72 लाख हेक्टेयर में गिरावट आई है। पिछले साल 32.97 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी जबकि इस साल अभी तक 32.25 लाख हेक्टेयर में बोवनी हुई है जबकि इसका नॉर्मल रकबा लगभग 39 लाख हेक्टेयर का रहा है। मूंग की बोवनी में लगभग ढाई लाख हेक्टेयर की गिरावट है। कुल्थी में 0.01 लाख हेक्टेयर की गिरावट है। अन्य दालों की बात करें तो इसमें भी 0.79 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई है।

मोटे अनाजों का रकबा देखें तो ज्वार में 1.46 लाख हेक्टेयर की कमी, बाजरे में 0.40 की तेजी, रागी में 0.46 लाख हेक्टेयर की कमी, छोटे मिलेट में 0.61 लाख हेक्टेयर की वृद्धि, मक्के में 2.4 लाख हेक्टेयर की तेजी है। इसके अलावा तिलहन में इस बार 2.12 लाख हेक्टेयर की गिरावट है। मूंगफली में डेढ़ लाख हेक्टेयर की कमी, सोयाबीन में 1.26 लाख हेक्टेयर की वृद्धि, मूंगफली में 1.30 लाख हेक्टेयर की कमी, तिल में 0.97 लाख हेक्टेयर की कमी, नाइजर में 0.25 लाख हेक्टेयर की कमी, अरंडी में 0.72 लाख हेक्टेयर की तेजी और अन्य तिलहन में 0.04 लाख हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा गन्ने के रकबे में 4.26 लाख हेक्टेयर की वृद्धि है जबकि जूट और मेस्टा में 0.40 लाख हेक्टेयर की गिरावट है। कपास में भी 4.07 लाख हे. की गिरावट दर्ज की गई है।

धान का रकबा

पिछले वर्ष की इसी अवधि 398.58 लाख हेक्टेयर की तुलना में 409.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बोवनी की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 10.83 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र कवर किया गया है। बिहार 4.79 लाख हेक्टेयर, झारखंड 2.92 लाख हेक्टेयर, प. बंगाल 2.02 लाख हेक्टेयर, छग 1.57 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश 1.48 लाख हेक्टेयर, हरियाणा 1.29 लाख हेक्टेयर, यूपी 1.23 लाख हेक्टेयर, पंजाब 0.32 लाख हेक्टेयर, राजस्थान 0.10 लाख हेक्टेयर, तेलंगाना 0.07 लाख हेक्टेयर, नागालैंड 0.04 लाख हेक्टेयर, मेघालय 0.04 लाख हेक्टेयर, गुजरात 0.03 लाख हेक्टेयर, केरल 0.02 लाख हेक्टेयर, मिजोरम 0.01 लाख हेक्टेयर और अरुणाचल प्रदेश 0.01 लाख हेक्टेयर में अधिक बोवनी हुई है। दूसरी ओर कर्नाटक 1.42 लाख हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश 1.28 लाख हेक्टेयर, ओडिशा 0.83 लाख हेक्टेयर, तमिलनाडु 0.56 लाख हेक्टेयर, असम 0.50 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र 0.17 लाख हेक्टेयर, त्रिपुरा 0.11 लाख हेक्टेयर, मणिपुर 0.04 लाख हेक्टेयर, उत्तराखंड 0.03 लाख हेक्टेयर और जम्मू-कश्मीर 0.01 लाख हेक्टेयर में कम बोवनी हुई है।

दलहन का रकबा

पिछले वर्ष की इसी अवधि 127.57 लाख हेक्टेयर की तुलना में दलहन के अंतर्गत लगभग 121.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज दर्ज किया गया है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 6.57 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र कवर किया गया है। राजस्थान 1.31 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश 0.65 लाख हेक्टेयर, झारखंड 0.14 लाख हेक्टेयर, जम्मू-कश्मीर 0.10 लाख हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ 0.10 लाख हेक्टेयर, बिहार 0.06 लाख हेक्टेयर और पश्चिम बंगाल 0.01 लाख हेक्टेयर में अधिक खेती हुई है। दूसरी ओर, कर्नाटक 3.37 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र 2.66 लाख हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश 0.67 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश 0.50 लाख हेक्टेयर, गुजरात 0.45 लाख हेक्टेयर, तेलंगाना 0.43 लाख हेक्टेयर, तमिलनाडु 0.32 लाख हेक्टेयर, ओडिशा 0.26 लाख हेक्टेयर, हरियाणा 0.13 लाख हेक्टेयर, असम 0.07 लाख हेक्टेयर, त्रिपुरा 0.05 लाख हेक्टेयर और पंजाब 0.03 लाख हेक्टेयर में दालों की कम बोवनी हुई है।

तिलहन का रकबा

पिछले वर्ष की इसी अवधि (194.33 लाख हेक्टेयर) की तुलना में तिलहन के तहत लगभग 192.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज की सूचना दी गई है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 2.12 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र कवर किया गया है। उच्च कवरेज वाले राज्यों में महाराष्ट्र (1.46 लाख हेक्टेयर), राजस्थान (0.81 लाख हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (0.52 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.17 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (0.13 लाख हेक्टेयर), ओडिशा (0.13 लाख हेक्टेयर), मिजोरम (0.02 लाख हेक्टेयर), झारखंड (0.01 लाख हेक्टेयर), छत्तीसगढ़ (0.01 लाख हेक्टेयर), उत्तराखंड (0.01 लाख हेक्टेयर) और जम्मू और कश्मीर (0.01 लाख हेक्टेयर) के नाम हैं। दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश (2.63 लाख हेक्टेयर), कर्नाटक (2.06 लाख हेक्टेयर), तमिलनाडु (0.37 लाख हेक्टेयर), बिहार (0.12 लाख हेक्टेयर), गुजरात (0.10 लाख हेक्टेयर), असम (0.06 लाख हेक्टेयर), त्रिपुरा (0.02 लाख हेक्टेयर), सिक्किम (0.02 लाख हेक्टेयर), पंजाब (0.01 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.01 लाख हेक्टेयर) और अरुणाचल प्रदेश (0.01 लाख हेक्टेयर) में तिलहन की कम बोवनी हुई है।

गन्ने का रकबा

पिछले वर्ष की इसी अवधि (55.65 लाख हेक्टेयर) की तुलना में लगभग 59.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने का कवरेज दर्ज किया गया है. इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 4.26 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र कवर किया गया है. उच्च क्षेत्र वाले प्रदेशों में उत्तर प्रदेश (3.91 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (0.91 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.29 लाख हेक्टेयर), पंजाब (0.16 लाख हेक्टेयर), तमिलनाडु (0.08 लाख हेक्टेयर), ओडिशा (0.01 लाख हेक्टेयर) और असम (0.01 लाख हेक्टेयर) के नाम हैं। गुजरात (0.40 लाख हेक्टेयर), बिहार (0.11 लाख हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (0.10 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (0.08 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.05 लाख हेक्टेयर), कर्नाटक (0.04 लाख हेक्टेयर), उत्तराखंड (0.02 लाख हेक्टेयर), पश्चिम बंगाल (0.01 लाख हेक्टेयर) और छत्तीसगढ़ (0.01 लाख हेक्टेयर) में कम रकबा दर्ज किया गया है।

मिलेगा झील और नेचुरल माहौल, एक बार में एक साथ 500 लोग करेंगे योगाभ्यास

ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय में बनेगा योगवन

ग्वालियर। जागत गांव हमार

जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर में योग को बढ़ावा देने के लिए एक योग वन तैयार किया जाएगा। 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 बीघा के स्थान में बनने वाले इस योगवन के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से मंजूरी मिल गई है।

यूजीसी सहित अन्य अथोरिटीज से स्वीकृति मिलते ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद यहां लोग एक साथ मिलकर योग अभ्यास कर सकेंगे। स्थान की बात करें तो निर्माण के लिए जेयू के प्रशासनिक भवन के सामने मौजूद पार्क को योगवन बनाने के लिए चुना गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ साथ यह योग वन माहौल भी वैसा ही देगा जैसे मानों कि किसी शांत वन में बैठकर योग का अभ्यास किया जा रहा हो। खास बात यह है कि इस सुविधा का लाभ न सिर्फ विश्वविद्यालय के सदस्य और छात्र छात्रा ले सकेंगे बल्कि शहरवासी भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

पेड-पौधे और झीलें भी होंगी

योग वन को बनाने के पीछे का उद्देश्य ही प्रकृति के करीब आना है। इस योगवन में काफी कुछ खास चीजें होंगे जो कहीं न कहीं छात्रों सहित शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगी। इस योगवन को पेड़-पौधों से सुसज्जित किया जाएगा । इसके साथ ही छोटी सी कृत्रिम झील भी बनकर तैयार होगी जो बिलकुल ऐसा एहसास दिलाएगी मानो आप प्रकृति की गोद में बैठकर योग अभ्यास कर रहे हो।

500 लोग करेंगे योग

विश्वविद्यालय के इस प्रोजेक्ट को 6 बीघा में तैयार किया जा रहा है । इसमें एक समय पर लगभग 500 लोग योग अभ्यास कर सकेंगे। फ्लोर को भी विशेष रूप से डिजाइन किया जा रहा है। यह योग वन न सिर्फ सुविधाजनक होगा बल्कि इसको जिस हिसाब से डिजाइन किया जाना प्रस्तावित है , यह काफी आकर्षक भी लगेगा।

पावर प्लग आप्शन भी होंगे

बताया जाता है कि यहां योग करने के लिए लोगों को किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं होगी। आश्रित से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी योगा इंस्ट्रक्टर की गैरमौजूदगी में भी लोग यहां सिर्फ अपने लैपटाप की सहायता से योग अभ्यास कर सकते हैं। लैपटाप को पावर देने के लिए यहां विशेष रूप से पावर स्विच भी डिजाइन किए जाएंगे। जहां अपना लैपटाप कनेक्टर कर लोग देख देख कर योग अभ्यास कर सकेंगे। संभवत: जिले में इस तरह का प्रयोग पहली बार होने जा रहा है।

जल प्रदाय योजनाओं का समय-सीमा में हो क्रियान्वयन: सीएम

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के संचालक मंडल की बैठक हुई। बैठक में खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने विभिन्न नगरीय निकायों में संचालित जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश की अग्रणी स्थिति के लिए उन्होंने विभाग के अधिकारियों को बधाई दी। 27 सितंबर को इंदौर में पुरस्कार कार्यक्रम प्रस्तावित है। बैठक में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, मऊगंज जलप्रदाय परियोजना, पेटलावद जलप्रदाय, परियोजना खरगोन जलप्रदाय परियोजना, मिनी स्मार्ट सिटी परियोजना, सीधी सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई।

केंद्रीय मत्स्य-पालन, पशुपालन मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला बोले-गत 3 वर्षों में मध्यप्रदेश में मत्स्य-उत्पादन में 3 गुना वृद्धि

मत्स्य-उत्पादन में मप्र ने की उल्लेखनीय वृद्धि वैश्विक रैंकिंग बनाए रखने करें झींगा पालन

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तीसरी वर्षगांठ पर हुआ कार्यक्रम

भोपाल। जागत गांव हमार

केन्द्रीय मत्स्य-पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला ने कहा है कि गत 3 वर्षों में मध्यप्रदेश में मत्स्य-उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य-संपदा योजना और मछुआरा क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से मत्स्य-उत्पादन बढ़ा है और मछुआरों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्री रूपाला ने इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार को बधाई दी।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा भोपाल में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। पार्क में अनुसंधान केन्द्र, प्र-संस्करण सुविधा, जल पर्यटन, सजावटी मत्स्य-पालन जैसी सुविधाएं होंगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तटीय मत्स्य-पालन अधिनियम (कोस्टल एक्वाकल्चर एक्ट) के संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। भारत को अपनी वैश्विक रैंकिंग को बनाए रखने के लिए झींगा पालन को बढ़ावा देना चाहिए।

प्रधानमंत्री मत्स्य-संपदा योजना के देश में क्रियान्वयन के सफल 3 वर्ष पूरे होने पर आज ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आयोजित हुआ। कायक्रम का शुभारंभ केन्द्रीय मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला और प्रदेश के जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया। केन्द्रीय मत्स्य-पालन राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान एवं डॉ. एल मुरूगन, अध्यक्ष मध्यप्रदेश मत्स्य कल्याण बोर्ड सीताराम बाथम, अरूणाचल प्रदेश के कृषि बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य-पालन मंत्री तागे ताकी और सांसद शंकर लालवानी उपस्थित थे।

मत्स्य-पालन के क्षेत्र में उपलब्धि

जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में मछुआ समुदाय का योगदान सराहनीय है। मछुआ समुदाय का चहुंमुखी विकास जरूरी है और मध्यप्रदेश सरकार इसके लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सफल क्रिया-न्वयन से गत 3 वर्षों में मछुआ समाज के कल्याण और मत्स्य-पालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है।

239 नई परियोजनाएं स्वीकृत

केन्द्रीय मंत्री रूपाला ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिये पीएमएमएसवाय में 103 करोड़ 11 लाख रुपए लागत की 239 नयी मत्स्य-पालन परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन परियोजनाओं में झींगा पालन, मोती पालन, केज कल्चर, कोल्ड स्टोरेज आदि के क्षेत्र में कार्य होगा। रूपाला ने कार्यक्रम स्थल पर मत्स्य पालन प्रदर्शनी का शुभारंभ और भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति यात्रा संबंधी पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रदर्शनी स्टॉलों में भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय मत्स्य पालन पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय मत्स्य-पालन संस्थान और नॉटिकल इंजीनियरिंग संस्थान की गतिविधियों के साथ-साथ विभिन्न उद्यमियों द्वारा बेचे जा रहे जाल, चारा, मूल्य वर्धित उत्पादों आदि को प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम में 35 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों, 239 परियोजना लाभार्थियों, मत्स्य-पालन सहकारी समितियों, सागर मित्र, राज्य मत्स्य-पालन संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। केन्द्रीय मत्स्य-पालन सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी और केन्द्रीय संयुक्त सचिव डीओएफ सागर मेहरा ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एनएफडीबी के सीई डॉ. एलएन मूर्ति ने आभार माना।

किसानों के लिए सम-समायिकी सलाह

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केन्द्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके . जाटव, द्वारा किसानों को सम-समायिकी सलाह के रूप में उड़द एवं मूंग की फसल पकने की अवस्था में है। इस समय वर्षा हो रही है। साफ मौसम को देखते हुये फसल की कटाई कर लें और सुरक्षित स्थान पर रखें। सोयाबीन फसल में दाना बनने की अवस्था में कीट व्याधियां हो रही है तो सोयाबीन में

गर्डेल वीटल को नियंत्रण के लिये स्पेनोसेड 45 प्रतिशत एससी दवा की 2 एमएल प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तिल की फसल में जैसिड, तिल हॉक मोथ एवं सफेद मक्खी का प्रकोप हो इसके लिये 0.5 एमएल इमिडाक्लोरोप्रिड या प्रोपोनोफॉस 2 मिली दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अरबी में पत्ती धब्बा रोग की संभावना को देखते हुये किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए मेक्टालाक्जिल 1 ग्राम कोजेब 2 ग्राम दवा का प्रतिलीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पपीता की फसल में तना सड़न रोग से बचाव के लिये बोडो मिश्रण या फफूंदनाशक ट्यूबोकोनोजॉल 2.0 एमएल प्रति लीटर पानी कर दर से दवा का 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। किसान भाइयो का सलाह दी जाती है कि वे बकरियों को बारिश में भीगने से बचायें अन्यथा उन्हे निमोनियां और डायरिया रोग हो सकता है।

खेती में कीट नियंत्रण के लिए किसान कर रहे सोलर लाइट ट्रेप का उपयोग

बालाघाट। जागत गांव हमार

जिले में धान की पैदावार काफी अच्छी होती है। किसानों को धान एवं अन्य फसलों में कीट नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सौर ऊर्जा आधारित सोलर लाइट ट्रेप उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के ग्राम कटंगझरी के किसान वीरेन्द्र धान्द्रे एवं अन्य किसान सफलतापूर्वक सोलर लाइट ट्रेप का उपयोग कर रहे हैं।

सोलर लाइट ट्रेप खेत में एक स्थान पर रखा जाता है। इस यंत्र में अल्ट्रावायलेट लाइट लगी रहती है। दिन में सूर्य के प्रकाश में पेनल द्वारा ऊर्जा एकत्रित होती है और अंधेरा होने पर सेंसर के कारण यंत्र में लाइट चालू हो जाती है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ट्रेप में कीटों के आने के बाद कीट नीचे लगी जाली में फंस जाते हैं। इस प्रकार खेत में किसानों को तना छेदक तितली और अन्य कीटों से फसलों को बचाने में मदद मिलती है। किसान बगैर कीटनाशक दवाओं के उपयोग से फसल को बचाने में सफल हो जाते हैं। किसान खेतों में इस यंत्र को बांस के सहारे खड़ा करते हैं। एक कृषि यंत्र 3 से 5 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। दिन में सोलर पेनल द्वारा बेट्री चार्ज होती है। किसानों को यह यंत्र 2500 से 3500 हजार रुपए तक बाजार में उपलब्ध रहता है। किसानों को प्रति हेक्टेयर 500 रुपए अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

मध्यप्रदेश में है प्रति दिन प्रति व्यक्ति 591 ग्राम दूध की उपलब्धता

भोपाल। भारत को दुग्ध उत्पादन में सर्वोच्च स्थान दिलाने में मध्यप्रदेश का भी अति महत्वपूर्ण योगदान है। कुल 17 हजार 999 मीट्रिक टन के साथ प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। प्रदेश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 591 ग्राम प्रतिदिन है। यह उपलब्धता राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 444 ग्राम से 147 ग्राम अधिक है। मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन में लगातार बढ़ोत्तरी पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य, सुरक्षा और विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप हुई है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रथम चरण में 25 लाख 63 हजार और द्वितीय चरण में 208 लाख गौ-भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया गया, जो देश में सर्वाधिक है। गौ-भैंस वंशीय पशु बछिया/पड़िया में 13 लाख 89 हजार ब्रुसेल्ला टीकाकरण में भी प्रदेश, देश में प्रथम है। देश में सबसे अधिक 3 लाख 77 हजार पशु पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करने वाला राज्य भी मध्यप्रदेश है। प्रदेश में अब तक 36 लाख 47 हजार 482 पशुओं का लम्पी के विरूद्ध टीकाकरण किया जा चुका है। यही वजह रही कि पड़ोसी राज्यों में लम्पी की वर्ष 2022 में वीभत्सता के बावजूद सतर्कता के चलते मध्यप्रदेश में 29 हजार 413 पशु प्रभावित हुए। इनमें से 27 हजार 726 पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ।

किसान लगवा सकेंग ट्रांसफार्मर, आधा खर्च उठाएगी राज्य सरकार

शिवराज कैबिनेट का फैसला-सीएम कृषक मित्र योजना मंजूर, किसानों को 200 मीटर दूरी तक के लिए बिजली के नए कनेक्शन आसानी से दिए जाएंगे

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में किसान या किसानों के समूह को तीन हार्सपावर या उससे अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिए जाएंगे। ट्रांसफार्मर उनके खेतों में लगाए जाएंगे। इसके लिए शिवराज सरकार ने शनिवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लागू करने का निर्णय लिया है। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में किसानों को बिजली के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया। योजना लागू होने से दो वर्ष तक प्रभावी रहेगी। प्रथम वर्ष में दस हजार कृषि पंपों का लक्ष्य रखा गया है। स्थायी पंप कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 किलोवाट लाइन का विस्तार करेगी और ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा किसान या किसानों के समूह द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत राशि शासन एवं 10 प्रतिशत राशि का भार विद्युत वितरण कंपनी उठाएगी।

» मुरैना में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क मोड में स्वीकृत
» 1400 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज आधारित हाइब्रिड पार्क के लिए सौर पार्क परियोजना विकसित होगी।
» जनजातीय कार्य विभाग में सीएम राइज योजना के अंतर्गत 10 विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 323 करोड़ 13 लाख की स्वीकृति।
» युवा उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने नीमच के जावद में बायोटेक्नोलाजी पार्क की स्थापना होगी।
» जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र भवनों का निर्माण एवं आधुनिकीकरण योजना में आगामी तीन वर्ष में 27 करोड़ का व्यय होंगे।

प्रदेश के आहत किसानों को सरकार देगी राहत

इधर, सीहोर जिले के अमलाहा में सीएम ने जनसभा में घोषणा की कि जिन किसानों की फसल क्षति हुई है, उनका सर्वे कराकर बीमा कम्पनी और सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। किसान भाई चिंता न करें। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत केन्द्र द्वारा 6000 रुपए दिए जाते है, अब प्रदेश सरकार की ओर से भी किसान कल्याण योजना के तहत 6000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। इससे किसानों को 12000 रुपए मिल रहे हैं।

मध्यप्रदेश में चलाई जा रही सब्जी विस्तार योजना

सब्जियां लगाने पर किसानों को मिलेंगे 30 हजार अनुदान

किसानों को 50 फीसदी तक अनुदान देगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिवराज सरकार द्वारा सब्जी विस्तार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को सब्जी लगाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देती है। योजना के तहत बीज वाली फसल भिंडी, गिलकी, लौकी, टमाटर, कद्दू, ककड़ी, जैसी फसलों को शामिल किया गया है। सब्जी विस्तार योजना का लाभ सामान्य, एससी, एसटी और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को दिया जाएगा।

इस तरह मिलेगा लाभ: योजना के तहत किसानों को लगाई गई फसल की लागत की 50 फीसदी राशि अधिकतम 10 हजार रुपए अनुदान के तौर पर दी जाती है। इसके अलावा जड़ अथवा व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करने पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 30 हजार रुपए किसानों को अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। किसान चाहे तो कितने भी क्षेत्र में सब्जियों की खेती कर सकते हैं, लेकिन किसानों को न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर पर उगाई गई फसलों पर ही अनुदान दिया जाएगा।

पहले आओ पहले पाओ

किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद संबंधित अधिकारी किसानों की भूमि पर पहुंचेंगे और सिंचाई और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी देंगे। जानकारी लेने पर किसान का नाम पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।

यह है प्रक्रिया

योजना के तहत उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जो कि पूर्व से विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। किसानों को खुद की निजी भूमि होने पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा। वन अधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन के खसरा की फोटोकापी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, अधिक जानकारी और आनलाइन आवेदन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

मप्र में किसानों को फिर मिलेगा फसल बीमा

-खरीफ का 700 करोड़ का किया जाएगा भुगतान

-रबी फसलों के दावों को अंतिम रूप दिया जा रहा

भोपाल। विधानसभा चुनाव के पहले किसानों को फिर फसल बीमा मिलेगा। वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी की फसलों को प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान हुआ था, उसका सर्वे कर क्षतिपूर्ति के दावे बीमा कंपनियों को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 27 या 28 सितंबर को कार्यक्रम हो सकता है। सरकार ने जून-2023 में किसानों को वर्ष 2021 के फसल बीमा का दो हजार 900 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। अब वर्ष 2022 का भुगतान किया जाना है। खरीफ फसलों को अतिवर्षा से नुकसान पहुंचा था। इसमें भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, हरदा सहित अन्य जिलों में फसलें अधि प्रभावित हुई थीं। कृषि विभाग ने क्षतिपूर्ति दिलाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सूत्रों के अनुसार खरीफ फसलों के लिए लगभग सात सौ करोड़ रुपए का भुगतान किया जा सकता है। जबकि, रबी फसलों के दावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

किसानों से 30 लाख की उपज खरीदी और भुगतान किए बिना व्यापारी फरार

बैतूल। जिले के बडोरा स्थित कृषि उपज मंडी में 21 किसानों से 30 लाख रुपए की उपज खरीदी करने के बाद व्यापारी बिना भुगतान किए फरार हो गया है। किसानों ने मंडी प्रबंधन के बाद अब कलेक्टर से भुगतान दिलाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि मंडी प्रबंधन द्वारा नकद भुगतान की व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है जिससे व्यापारी उपज की खरीदी करने के कई दिन बाद तक भुगतान करते हैं। इसी का फायदा उठाकर एक पंजीकृत व्यापारी खरीदी कर भाग गया। किसानों ने कलेक्टर से व्यापारी की संपत्ति कुर्क कर भुगतान दिलाने की मांग की है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 21 किसानों द्वारा कृषि उपज मंडी बडोरा में गेहूं बेचने के लिए लाया गया था। मंडी में हरि ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा उपज की बोली लगाकर खरीदी कर ली गई।

भुगतान का आश्वासन

भुगतान के लिए किसानों को एक दो दिन बाद आने का कह दिया गया। मंडी में लंबे समय से खरीदी कर रहे व्यापारी पर किसानों ने भरोसा कर लिया और इंतजार करने लगे। कुछ दिन बाद तो व्यापारी ने मंडी में खरीदी करना ही बंद कर दिया और गायब हो गया।

शिकायत के बाद छानबीन

जब मंडी सचिव और प्रशासक से इसकी शिकायत की तब वे हरकत में आए। किसानों की ओर से बैतूल बाजार थाने में व्यापारी के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया। पुलिस भी किसानों की राशि लेकर भागे व्यापारी को अब तक तलाश नहीं कर पाई है। हालत यह है कि किसान मंडी सचिव, प्रशासक, कलेक्टर और पुलिस के पास भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें भुगतान ही प्राप्त नहीं हो सका है। किसानों की नाराजगी बढ़ती देख मंडी प्रबंधन के द्वारा व्यापारी का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई कर दी गई है। इसके अलावा संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी की जा रही है। मंडी सचिव शीला खातरकर ने बताया कि किसानों को भुगतान न करने के कारण हरि ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)